

स्वस्थ रहो, आत्मनिर्भर

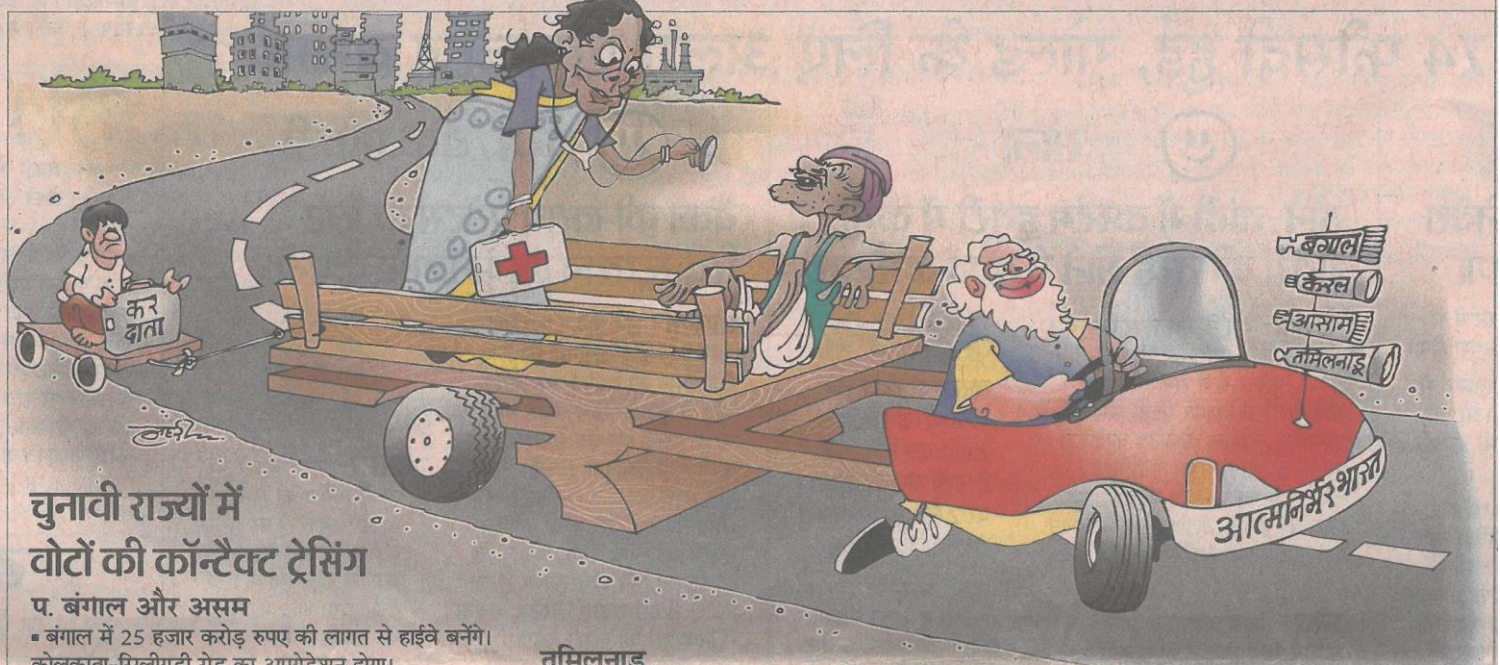
■ मध्यम वर्ग को सीधी राहत नहीं, लेकिन कोरोना संकट के बावजूद किसी वर्ग पर अतिरिक्त टैक्स नहीं

■ ईपीएफ में सालाना 2.5 लाख रु. से ज्यादा जमा पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स के दायरे में

■ सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले ऑटो मोबाइल, रियल एस्टेट व टेक्सटाइल सेक्टर को मिला बूस्टर

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

मोदी सरकार का कोरोनाकाल का पहला बजट बहुत ज्यादा लोकलुभावन भले न दिखे, मगर खर्च और बचत का संतुलन साधता जरूर दिख रहा है। सेहत की फिक्र के साथ ही इसमें रोजगार बढ़ाने के लिए करीब 17 करोड़ नौकरियां देने वाले सेक्टर ऑटो, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट पर ज्यादा फोकस किया गया है। ऑटो सेक्टर में नई वाहन स्क्रेप पॉलिसी से जहां बाजार में नई डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, वहीं स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटने से निर्माण लागत भी कम होने के आसार हैं। टेक्सटाइल के लिए जहां 7 नए मेगापार्क की घोषणा हुई है, वहीं रॉ कॉटन और यार्न का आयात महंगा कर घरेलू बाजार को बूस्ट दिया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी स्टील आयात सस्ता होने से लागत घटेगी, वहीं अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्स हॉलीडे की समयसीमा भी एक साल बढ़ा दी गई है। हालांकि, मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है। ईपीएफ में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा जमा पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में लाकर वेतनभोगियों को झटका भी दिया है। हालांकि अर्थव्यवस्था के मुश्किल दौर में भी कोई नया टैक्स न लाना आम करदाता के लिए बड़ी राहत जैसा ही है। अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए जहां बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 74% करने की घोषणा हुई है, वहीं दो और सरकारी बैंकों के विनिवेश का भी फैसला लिया गया है। ऊर्जा सेक्टर में गुणवत्ता सुधारने के लिए इस बजट में बिजली उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता और वितरण कंपनी चुनने की सुविधा दी गई है। जल्द इसकी रूपरेखा तैयार होगी।



चुनावी राज्यों में वोटों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग

प. बंगाल और असम

- बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा।
- दोनों ही राज्यों के चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ का फंड घोषित किया गया है।
- असम में 34 हजार करोड़ एनएच निर्माण पर खर्च होंगे।

तमिलनाडु

- चेन्नई में 63 हजार करोड़ रु. का मेट्रो प्रोजेक्ट। 180 किमी लंबा रूट होगा।
- 3500 किमी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत 1.03 लाख करोड़ रु. खर्च होंगे।

केरल

- राज्य में 1100 किमी एनएच बनेंगे। मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर बनेगा।
- केरल में इस प्रोजेक्ट पर कुल 65 हजार करोड़ रु. खर्च होंगे।
- कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ से 11 किमी का हिस्सा बनाया जाएगा।

यूं बनेंगे आत्मनिर्भर...

सरकार ने हर उस वस्तु का आयात महंगा किया जो देश में बन सकती है

■ सरकार ने लंबे समय बाद कस्टम व एक्साइज ड्यूटी में काफी बदलाव किए हैं। फौरी तौर पर देखा जाए तो इससे मोबाइल, मोबाइल चार्जर, फ्रिज-एसी व साइकिल जैसी चीजें महंगी होती नजर आ रही हैं। मगर बारीकी से देखा जाए तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ाया कदम है।

■ सरकार ने एथाइल एल्कोहल का आयात महंगा किया है। इससे बनने वाले एथेनॉल का इस्तेमाल क्लीन फ्यूल बनाने में करने की कवायद जारी है। पेट्रोल में 22% तक एथेनॉल मिलाया जा सकता है, अभी देश में 10% ही मिलाया जा रहा है। देश में गन्ना, मक्का और धान जैसी फसलों के अवशेष उत्पाद से एथेनॉल बनाया जा सकता है। ऐसे में इसका आयात महंगा करना घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाएगा।

■ सरकार ने कूड पाम ऑयल, कूड सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का आयात महंगा किया है। इससे घरेलू खाद्य तेल निर्माता कंपनियों को देश की ही उपज पर फोकस करना होगा।

■ सरकार ने स्टील-आयर्न स्क्रेप का आयात सस्ता किया है, जबकि स्क्रू, नट-बोल्ट का आयात महंगा कर दिया है। यानी कच्चे माल का आयात तो सस्ता होगा, मगर तैयार माल का आयात महंगा होगा। यह कदम चीन की बाजार नीति पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है।

■ ऑटोमोबाइल सेक्टर में कुछ कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है जिससे लगजरी गाड़ियों की कीमत बढ़ सकती है, मगर साथ ही स्टील का आयात सस्ता किया है। इससे वाहन निर्माण की कुल लागत अब पहले से कम हो सकती है।

सोना-चांदी सस्ते, मोबाइल-फ्रिज महंगे

कस्टम ड्यूटी बढ़ने से ये महंगे :

- जेम्स एंड ज्वेलरी ■ फ्रिज, एसी कंप्रेसर
- इम्पोर्टेड सेब ■ कूड पाम ऑयल ■ कूड सोयाबीन ऑयल ■ कूड सनफ्लावर ऑयल ■ मटर ■ काबुली चना ■ देसी चना ■ मसूर दाल ■ शराब ■ कोयला

- रॉ कॉटन-यार्न ■ स्क्रू, नट-बोल्ट
- वायर-केबल ■ मोबाइल के पार्ट्स
- मोबाइल चार्जर ■ एलईडी ■ सोलर लैंप व इनवर्टर ■ इलेक्ट्रॉनिक खिलौने
- साइकिल ■ कुछ ऑटो पार्ट्स ■ कोल
- लिग्नाइट ■ पीट

और ये सस्ते हुए : ■ सोना ■ मिश्रित सोना ■ चांदी ■ कीमती धातु जैसे प्लेटिनम ■ आयरन-स्टील स्क्रेप ■ स्टेनलेस स्टील। बजट घोषणा के बाद सोना 1896 रु. टूटा।

कृषि बजट घटा, पर सेस जुड़ा...

पेट्रोल पर 2.5 व डीजल पर 4 रु. सेस, पर कीमत नहीं बढ़ेगी

खेती का बजट 1.42 लाख करोड़ से घटकर 1.31 लाख करोड़ हो गया है। मगर सरकार ने 12 चीजों की कस्टम ड्यूटी पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है। सिर्फ इस सेस से होने वाली कमाई ही कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकती है। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर भी यह सेस क्रमशः 2.50 रुपए और 4 रुपए लगाया गया है। हालांकि पेट्रो उत्पादों पर बेसिक एक्साइज ड्यूटी इतनी ही कम कर दी गई है। इससे उपभोक्ता पर तो कोई भार नहीं पड़ेगा।

इनकी ड्यूटी पर सेस

सोना-चांदी	2.5%
शराब	100%
सेब	35%
दूरिया	5%
मटर	40%
काबुली चना	30%
देसी चना	50%
मसूर	20%
कॉटन	5%

निवेश-विनिवेश... बीमा क्षेत्र में अब 74%

एफडीआई, बड़े प्रोजेक्ट्स का निजीकरण भी

सरकार ने विनिवेश लक्ष्य 1.75 लाख करोड़ रखा है। बीमा कंपनियों में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। सरकार एलआईसी

का आईपीओ लाएगी। दो सरकारी बैंकों और एक जनरल इश्योरेंस कंपनी में विनिवेश होगा। बंदरगाह, एयरपोर्ट्स और फ्रेट कॉरिडोर के निजीकरण पर भी जोर।

सब्सिडी... रसोई गैस पर सब्सिडी का फंड 62% घटाया, लेकिन खाद्य सब्सिडी दोगुनी की

सरकार ने पहली बार केरोसिन पर सब्सिडी खत्म की है। साथ ही एलपीजी पर सब्सिडी 62.2% घटाई है। लेकिन, खाद्य सब्सिडी 110% बढ़ा दी गई है।

इसका सीधा असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बंटने वाले मुफ्त या सस्ते राशन पर पड़ेगा। अभी 50 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

फ्लैगशिप योजना... मनरेगा का फंड 15% बढ़ा, पीएम किसान सम्मान निधि इतनी ही घटा दी

सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं में आवंटन बदला है। गांवों में पानी पर खर्च बढ़ाया गया है। मनरेगा का बजट 15.8% बढ़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का 15.4% घटा है।